ECONOMIC TIMES, Delhi, 25.3.2023
Page No. 7, Size:(9.13)cms X (2.96)cms.

New Deadline for Oil & Gas Exploration Licences

Our Bureau

New Delhi: The government has once again extended the deadline for accepting bids in the eighth oil and gas exploration licensing round, to May 16, the Directorate General of Hydrocarbons (DGH) said on its website. The eighth round under the open acreage licensing policy was launched on July 7, with a bid submission deadline of September 6. Since then, the deadline has been extended several times. The last deadline was March 30.

FINANCIAL EXPRESS, Delhi, 25.3.2023
Page No. 2, Size:(3.12)cms X (18.38)cms.

Windfall tax: Vedanta holds back $91 mn from govt's profit

AMMAR ZAIDI
New Delhi, March 24

IN SIGNS OF protests against the nine-month-old windfall tax, mining mogul Anil Agarwal's Vedanta has withheld about $91 million from the share of profit due to government from its oil and gas fields, to make up for the additional tax outgo, according to sources and correspondence on the issue.

India first imposed windfall profit tax on July 1, 2022 joining a growing number of nations that tax super normal profits of energy companies. But the levy of special additional excise duty (SAED) on locally produced crude oil was seen by producers as violation of the contract which provides fiscal stability.

The SAED initially was ₹23,250 per tonne ($40 per barrel) and in fortnightly revisions brought down to ₹3,500 per tonne. This is in addition to 10-20% royalty on price of oil and gas realised and an oil cess of 20%.

Vedanta on January 31 and on February 20 informed the ministry of petroleum and natural gas that it has made a deduction of $85.35 million for SAED paid on its prolific Rajasthan block, RJ-ON-90/1, and another $5.50 million for block CB-OS/2 in Cambay basin.

This was being done to restore economic benefits as mentioned in the signed contracts under which it operates, the correspondence, reviewed by *PTI*, showed.

It argued that the contracts, called production sharing contract or PSC, provides for fiscal stability for the contracting parties. The PSC states that in the event of change of law or rule or regulation that results in adverse change to the expected economic benefits to any of the parties, the parties shall consult promptly and make necessary revisions and adjustments to the contract in order to maintain such expected economic benefits to each of them.

The ministry however in a February 22 letter called the "unilateral" deduction as "wrongful" and asked the company to pay the short paid profit along with interest within seven days. Vedanta has not complied with the direction.

Vedanta's Cairn Oil & Gas, which operates the two blocks, did not answer emails sent for comments. Emails sent to the oil ministry too remained unanswered. — PTI

FINANCIAL EXPRESS
READ TO LEAD

HARI BHOOMI, Delhi, 25.3.2023
Page No. 10, Size:(21.87)cms X (30.94)cms.

वेदांता ने नौ माह पहले लगाए अप्रत्याशित कर का विरोध किया था

अप्रत्याशित लाभ करः वेदांता ने सरकार के लाभांश से 9.1 करोड़ डॉलर काटे

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने नौ महीने पहले अप्रत्याशित लाभ कर लगाए जाने को लेकर एक तरह से विरोध जताते हुए कर चुकाने के लिए अपने तेल और गैस संयंत्रों से सरकार के लाभांश में से लगभग 9.1 करोड़ डॉलर रोक लिया है। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।

भारत ने एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया। इसके साथ उन देशों में शामिल हो गया, जिन्होंने ऊर्जा कंपनियों को हो रहे अच्छे लाभ को देखते हुए कर लगाया था। इसके अलावा स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया गया।

एसएईडी पहले 40 डॉलर प्रति बैरल लगी

स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को उत्पादनकर्ता वित्तीय स्थिरता प्रदान करने वाले अनुबंध का उल्लंघन मानते हैं। एसएईडी शुरू में 23,250 रुपये प्रति टन (40 डॉलर प्रति बैरल) की दर से लगाया गया।

ऊर्जा कंपनियों को हो रहे अच्छे लाभ के कारण लगाया कर

खास बातें

- अपने तेल और गैस संयंत्रों के लाभांश में से 9.1 करोड़ डॉलर रोके
- भारत ने एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया

आर्थिक लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका

पीएससी में कहा गया है कि कानून या नियम या विनियमन में अगर परिवर्तन होता है और उससे आर्थिक लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, उस स्थिति में संबंधित पक्ष तुरंत परामर्श करेंगे और इस तरह प्रत्येक के लिए अपेक्षित लाभ बनाए रखने को लेकर अनुबंध को आवश्यक संशोधन और समायोजन करेंगी।

तेल और गैस पर रॉयल्टी 20 फीसदी

पंद्रह दिन पर होने वाले संशोधनों में इसे घटाकर 3,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया। यह तेल और गैस की कीमत पर 10-20 प्रतिशत रॉयल्टी और 20 प्रतिशत का तेल उपकर के अलावा है।

मंत्रालय को सूचना देने की दी जानकारी

वेदांता ने 31 जनवरी को और 20 फरवरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित किया था कि उसने एसएईडी चुकाने के लिए राजस्थान ब्लॉक, आरजे-ओएन-90/1 पर 8.53 करोड़ डॉलर के अलावा कैम्बे बेसिन में ब्लॉक सीबी-ओएस/2 के लिए 55 लाख डॉलर की कटौती की है।

पीएससी वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है

मिले पत्र के अनुसार, कंपनी ने कहा कि यह अनुबंधों में उल्लेखित आर्थिक लाभ को बरकरार रखने के दृष्टिकोण के साथ किया गया। कंपनी ने तर्क देते हुए कहा कि उत्पादन साझेदारी अनुबंध (पीएससी) अनुबंधित पक्षों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है।

मंत्रालय ने एकतरफा कटौती बताया

मंत्रालय ने हालांकि 22 फरवरी को एक पत्र में इसे 'एकतरफा' कटौती बताते हुए इसे गलत बताया और कंपनी को सात दिनों के भीतर ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए कहा। हालांकि वेदांता ने दिशा का अनुपालन नहीं किया है।

मंत्रालय से नहीं मिली कोई प्रतिक्रिया

इस बारे में दोनों ब्लॉक का परिचालन करने वाली वेदांता के कयर्न ऑयल एंड गैस को ई-मेल भेजकर प्रतिक्रिया मांगी गयी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

BUSINESS STANDARD HINDI, Delhi, 25.3.2023
Page No. 5, Size:(25.27)cms X (16.07)cms.

गति शक्ति : निजी क्षेत्र हो सकता है मददगार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति नैशनल मास्टर प्लान की घोषणा अक्टूबर 2021 में की थी। यह योजना भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत देश में सभी आर्थिक क्षेत्रों एवं संकुलों को जोड़ने का प्रस्ताव है। इस प्लेटफॉर्म पर आधारभूत कड़ियां उपलब्ध हैं जो किसी संकुल को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए जरूरी होते हैं। इनमें रेल संपर्क, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, तेल एवं गैस पाइपलाइन, बिजली पारेषण लाइन, जल आपूर्ति पाइप आदि शामिल हैं।

गति शक्ति प्लेटफॉर्म परियोजना के ढांचे और क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म का विकास भास्कराचार्य नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस ऐप्लिकेशंस ऐंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) द्वारा किया गया है। बीआईएसएजी गांधीनगर स्थित स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है जो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करती है। यह संस्था उपग्रह संचार (सैटेलाइट कम्युनिकेशन), जियोइन्फॉर्मेटिक्स और भू-अंतरिक्ष तकनीक से संबंधित परियोजनाओं पर काम करती है। विभिन्न मंत्रालयों से प्रशिक्षित एवं प्रतिबद्ध अधिकारियों का दल वाणिज्य मंत्रालय में एक विशेष सेल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) में काम करते हैं। एनपीजी गति शक्ति से जुड़ी सभी गतिविधियों का ढांचा तैयार करता है।

गति शक्ति एक बड़ा बदलाव लाने वाली योजना है। इसके चार कारण हैं। पहला कारण, यह परियोजना ढांचा एवं क्रियान्वयन में पुराने तौर-तरीकों से अलग नई कार्य प्रणाली और केंद्र, राज्य, मंत्रालयों एवं विभागों के बीच एक एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। दूसरा कारण यह है कि इससे परियोजना से जुड़े प्रस्ताव शीघ्र करने में मदद मिलती है। तीसरा कारण यह है कि पूर्व में आधारभूत ढांचा मंत्रालय से जिन कार्यों को संपादित करने की अपेक्षा की गई थी उसे यह डिजिटल माध्यम से पूरा कर रहा है। चौथा कारण यह है कि गति शक्ति की मदद से इससे निजी क्षेत्र निवेश से जुड़े स्थान का चयन अपनी पसंद के अनुसार कर पाएगा।

सितंबर 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी (एनएलपी) की घोषणा के बाद एक बार फिर ध्यान इस ओर आया कि गति शक्ति योजना किसी तरह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में माल वहन पर आने वाला खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 13 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। एनएलपी के बाद यह कम होकर जीडीपी का 8 प्रतिशत तक रह सकता है। इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में विभिन्न नीतियां काम करेंगी मगर गति शक्ति प्लेटफॉर्म से मिलने वाली सहायता एवं नीति इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण होंगी।

बुनियादी ढांचा

विनायक चटर्जी

अब सवाल है कि हम गति शक्ति को लेकर कितनी प्रगति कर चुके हैं? अब तक जो जानकारी सार्वजनिक की गई है उनके अनुसार गति शक्ति में सूचनाओं की 1,300 श्रेणियां हैं। इनमें आधारभूत ढांचा पर्यावरण एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़ी बातें हैं। इनके अलावा सड़क रेलवे, बंदरगाह, हवाईअड्डा, बिजली, दूरसंचार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और अक्षय ऊर्जा से जुड़ी जानकारियां एकीकृत की गई हैं। इन सूचनाओं का इस्तेमाल एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए हो रहा है। गांव, तालुका, जिला स्तर तक की जानकारियों के साथ खसरा संख्या, आबादी वाले इलाकों की भौगोलिक स्थिति, 3डी प्रतिबिंब, मृदा की गुणवत्ता आदि से जुड़ी सूचनाएं भी उपलब्ध हैं। यह भी जानकारी सार्वजनिक की गई है कि 30 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने अलग से गति शक्ति से तालमेल रखने वाले पोर्टल तैयार किए हैं। ये पोर्टल गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जोड़ दिए गए हैं। गति शक्ति प्लेटफॉर्म का नियमित तौर पर इस्तेमाल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर लगने वाले समय को कम करने, भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी तरह की मंजूरी लेने और रैखिक बुनियादी ढांचे के मिलान के लिए हो रहा है। अब तक एनपीजी की 44 बैठकें हो चुकी हैं जिनमें जिनमें 66 उच्च प्रभाव वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इन परियोजनाओं पर कुल खर्च 5 लाख करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। गति शक्ति संरचना का इस्तेमाल कर अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कोयला, इस्पात एवं उर्वरक आदि के परिवहन और इसमें आने वाली समस्याओं की पहचान की जा चुकी है।

हाल में कुछ प्रमुख परियोजनाओं में गति शक्ति प्लेटफॉर्म की मदद से कई त्रुटियां दूर की गई है। इन परियोजनाओं में दिघी पोर्ट क्षेत्र गुरदासपुर-जम्मू कश्मीर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, चेन्नई तूतीकोरिन एक्सप्रेसवे और बड़बिल और बरसाना के बीच 181 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन शामिल हैं। बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री के अनुसार गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर कुल मिलाकर 100 महत्त्वपूर्ण बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की पहचान हो चुकी है और उनसे जुड़ी दिक्कतें दूर की जा रही हैं।

इस बात की भी चर्चा चल रही है कि गति शक्ति की मदद से प्रशासनिक ढांचे में जमीनी स्तर पर आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। अगर प्रत्येक आर्थिक संकुल वास्तव में गठित होता है और इसे संयोजित कड़ी का दर्जा दिया जाता है तो इन क्षेत्रों के लिए कलेक्टर की जगह एक अलग से विकास आयुक्त नहीं होना चाहिए? जिला कलेक्टर पर पहले से ही कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन विषयों पर गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर विचार होगा और उम्मीद की जा रही है कि पुराने तरीके से चलने वाले कामकाज की जगह आधुनिक एवं सरल पद्धति से प्रशासनिक कार्य निपटाए जाएंगे। यह भी देख कर बहुत खुशी हो रही है कि गति शक्ति की क्षमता को विपक्षी राज्य भी राष्ट्र निर्माण के रूप में देख रहे हैं।

हालांकि, सरकार अब भी गति शक्ति तक निजी इकाइयों की पहुंच और उनके द्वारा इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। इस समय गति शक्ति प्लेटफॉर्म तक सरकारी विभागों, राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के अधिकृत व्यक्तियों की ही पहुंच है। इसका कारण यह है कि गति शक्ति प्लेटफॉर्म में कई ऐसी संवेदनशील जानकारियां भी उपलब्ध रहती हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण होती हैं। हालांकि इस पर नागरिक समाज से जुड़े कई दिलचस्प विषय भी होते हैं जिन तक निजी उद्योग, परिवहन-माल ढुलाई पर शोध करने वाले लोग, छात्र एवं पत्रकारों की पहुंच होती है। कुछ गैर-सरकारी इकाइयों में इस बात का गुस्सा है कि उन्हें इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच की अनुमति नहीं है। ऐसा समझा जा रहा है कि सरकार इस ढांचे में कुछ बदलाव कर रही है जिससे निजी क्षेत्र को भी सीमित पहुंच मिल जाएगी। यह कार्य जितनी जल्दी किया जाएगा उतना ही अच्छा होगा। ऐसा करने से गति शक्ति प्लेटफॉर्म अधिक व्यापक हो जाएगा और यह अधिक प्रभावी भी हो जाएगा।

(लेखक आधारभूत क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। वह 'द इन्फ्राविजन फाउंडेशन' के संस्थापक एवं प्रबंध न्यासी भी हैं।)

HARI BHOOMI, Delhi, 25.3.2023
Page No. 1, Size:(21.89)cms X (30.97)cms.

केंद्रीय कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अब हर साल 12 सिलेंडर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैश्विक कारणों के कारण गरीब जनता पर बोझ न पड़े इसके लिए 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर और एक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय दामों में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे करीब 9.6 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। ▸▸ शेष पेज 7 पर

प्रधानमंत्री उज्ज्वला...

जूट के एमएसपी में 300 रुपये की बढ़ोतरी: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष जूट का एमएसपी 4,750 रुपए प्रति क्विंटल था, उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी करके इसको 5,050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

BUSINESS STANDARD HINDI, Delhi, 25.3.2023
Page No. 2, Size:(8.77)cms X (16.46)cms.

अप्रत्याशित लाभ कर का विरोध !

वेदांत ने सरकार के लाभांश में की कटौती

सरकार के लाभांश में से लगभग 9.1 करोड़ डॉलर की राशि रोकी

दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांत ने नौ महीने पहले अप्रत्याशित लाभ कर लगाए जाने को लेकर एक तरह से विरोध जताते हुए कर चुकाने के लिए अपने तेल और गैस संयंत्रों से सरकार के लाभांश में से लगभग 9.1 करोड़ डॉलर रोक लिया है। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।

भारत ने 1 जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया। इसके साथ उन देशों में शामिल हो गया, जिन्होंने ऊर्जा कंपनियों को हो रहे अच्छे लाभ को देखते हुए कर लगाया था। इसके अलावा स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया गया। लेकिन स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को उत्पादनकर्ता वित्तीय स्थिरता प्रदान करने वाले अनुबंध का उल्लंघन मानते हैं। एसएईडी शुरू में 23,250 रुपये प्रति टन (40 डॉलर प्रति बैरल) की दर से लगाया गया। 15 दिन पर होने वाले संशोधनों में इसे घटाकर 3,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया। यह तेल और गैस की कीमत पर 10-20 प्रतिशत रॉयल्टी और 20 प्रतिशत का तेल उपकर के अलावा है।

वेदांत ने 31 जनवरी को और 20 फरवरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित किया था कि उसने एसएईडी चुकाने के लिए राजस्थान ब्लॉक, आरजे-ओएन-90/1 पर 8.53 करोड़ डॉलर के अलावा कैम्बे बेसिन में ब्लॉक सीबी-ओएस/2 के लिए 55 लाख डॉलर की कटौती की है। एजेंसी को मिले पत्र के अनुसार, कंपनी ने कहा कि यह अनुबंधों में उल्लेखित आर्थिक लाभ को बरकरार रखने के दृष्टिकोण के साथ किया गया। कंपनी ने तर्क देते हुए कहा कि उत्पादन साझेदारी अनुबंध (पीएससी) अनुबंधित पक्षों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। *भाषा*

BUSINESS STANDARD HINDI, Delhi, 25.3.2023
Page No. 4, Size:(12.95)cms X (12.36)cms.

सीपीएसई ने पूंजीगत व्यय का 85 % खर्च किया

निकेश सिंह
नई दिल्ली, 24 मार्च

सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के पूंजीगत व्यय के खर्च के लक्ष्य वाले बड़े केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) ने वर्ष 2022-23 (वित्त वर्ष 23) के शुरुआती 11 महीनों के सालाना संशोधित अनुमानों के 85 फीसदी 6.46 लाख करोड़ रुपये के स्तर को प्राप्त कर लिया है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने दी।

इस पूंजीगत व्यय के लक्ष्य में पांच विभागों के 54 सीसीएसई हैं। तुलना करने पर पता चला कि सीपीएसई बीते वित्त वर्ष (2021-22 या वित्त वर्ष 22) में इस अवधि के दौरान केवल 79.28 फीसदी 5.95 लाख करोड़ का उपयोग कर पाया था। हालांकि वित्त वर्ष 22 की पूर्ण अवधि के दौरान संशोधित अनुमान का 96 फीसदी ही हासिल हो पाया था।

केंद्र के पूंजीगत व्यय से अधिक

इन सीपीएसई का पूंजीगत व्यय अधिक रहा। वित्त वर्ष 23 में अप्रैल-फरवरी के दौरान सीपीएसई ने 5.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे और उन्होंने वित्त वर्ष 22 की इस आलोच्य अवधि में 4.7 लाख करोड़ रुपयों का निवेश किया था। अधिकारी के अनुसार, ''54 सीपीएसई के संशोधित अनुमान 2.91 करोड़ रुपये से घटकर 2.41 करोड़ रुपये हुआ। उम्मीद यह है कि वे इस वर्ष के अंत तक संशोधित अनुमान के 96-97 फीसदी लक्ष्य को ही हासिल कर पाएंगे।''

अभी तक सीपीएसई में पूंजीगत व्यय का नेतृत्व पेट्रोलियम सीपीएसई और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने किया है। संशोधित अनुमान 6 फीसदी बढ़ाए जाने के बावजूद एनएचएआई अपने लक्ष्य का 104 फीसदी हासिल कर पाई है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी ऑयल ऐंड नेचुरल गैस कारपोरेशन बजट में आबंटित सालाना 29,950 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय में से केवल 82 फीसदी को ही प्राप्त कर पाई है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन (इंडियन ऑयल) ने महामारी के बाद पाइपलाइन परियोजनाओं और संशोधन की अपनी क्षमता में इजाफा करने के कारण सालाना संशोधित अनुमान 17,130 करोड़ रुपये का दोगुना हासिल किया। इस क्रम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी (एचपीसीएल) भी संशोधित अनुमान 7,163 करोड़ रुपये के 200 फीसदी के लक्ष्य को हासिल कर चुकी है।